

पाकिस्तान की परमाणु नीति, लक्ष्य एवं आवश्यकता भारत के संदर्भ में: एक समीक्षा

एस0 सी0 श्रीवास्तव

रक्षा अध्ययन विभाग, जे0 पी0 पी0 जी0 कालेज, वाराणासी.-यू0पी0.-221302

ARTICLE DETAILS

Article History

Published Online: 16 Nov 2019

Keywords

परमाणु कार्यक्रम, इस्लामिक बम, मुस्लिम-ब्लाक, क्षेत्रीय शक्ति एवं सामरिक श्रेष्ठता

Corresponding Author

Email: drsrivastava05[at]gmail.com

ABSTRACT

विश्व के विभिन्न मुस्लिम देशों से प्राप्त आर्थिक सहायता एवं अनेक पश्चिमी देशों से गोपनीय ढंग से आयातित तकनीकी ज्ञान व अपेक्षित कल पुर्जों के बल बूतों पर पाकिस्तान द्वारा रहस्यमयी ढंग से प्रारम्भ परमाणु बम निर्माण कार्यक्रम ने न केवल दक्षिण एशिया के स्ट्रातेजिक परिदृश्य को तनावयुक्त व दुविधा पूर्ण बना दिया है अपितु इस देश में परमाणु प्रसार की सम्भावनायें काफी प्रबल हो गयी हैं। "इस्लामिक बम" के निर्माण के पीछे पाकिस्तान की न केवल मुस्लिम जगत का नेतृत्व करने की दुराशा छिपी हुई है अपितु वह भारत पर सामरिक श्रेष्ठता हासिल करके कश्मीर सहित विभिन्न द्विपक्षीय मसलों पर भारत को ब्लैकमेल करना चाहता है। जहां एक ओर पाकिस्तान सम्पूर्ण मुस्लिम जगत को इस शक्ति से सुसम्पन्न करने की नीति पर चल रहा था वहीं इसकी आड़ में सम्पूर्ण इस्लामिक देशों का नेतृत्व करने की भी पाकिस्तानी महत्वाकांक्षी थी, जिससे विश्व-राजनीति में उसकी भूमिका को प्रमुखता मिल सके। इतना ही नहीं "मुस्लिम-ब्लाक" को विश्व-राजनीति में एक दबाव समूह के रूप में स्थापित करने की भी उसकी योजना है।

1 प्रस्तावना :-

वैसे तो पाकिस्तान के आणविक कार्यक्रम की शुरुआत सन् 1953 में ही हो गयी थी तथा 1968 तक उसपर 324 मिलियन डालर धनराशि का व्यय किया जा चुका था। किन्तु इस कार्यक्रम में पर्याप्त तीव्रता भारतीय परमाणु विस्फोट के बाद ही आयी। भुट्टों ने जेल के दौरान लिखी गयी पुस्तक "यदि मेरी हत्या कर दी जाती तो" में व्यापक रूप से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि "हम जानते हैं कि इजराइल एवं दक्षिण अफ्रीका के पास पूर्ण आणविक सामर्थ्य है, यहूदी, क्रिश्चियन तथा हिन्दू सभ्यतायें भी इस सामर्थ्य से सज्जित हैं, साम्यवादी देशों के पास भी यह शक्ति है। केवल इस्लामी सभ्यता ही इस सामर्थ्य से वंचित है लेकिन यह स्थिति भी इस समय परिवर्तित हो रही है। भुट्टों का उक्त कथन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि वे विभिन्न राजनैतिक व सामरिक कारणों से इस्लामिक जगत को परमाणु शस्त्र सामर्थ्य से सुसज्जित करने हेतु संकल्पबद्ध थे। यहां पर इस प्रश्न का गम्भीरता से विचार करना आवश्यक है कि पाकिस्तान ने इसे "पाकिस्तानी बम" के बजाय "इस्लामिक बम" का नामकरण क्यों दिया इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम ईरान के शाह, सऊदी अरब के किंग फैसल तथा बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री जुल्फिकार अली भुट्टों ने सम्पूर्ण मुस्लिम विश्व को एक सूत्र में बांधने की चेष्टा की थी। दूसरी ओर अरब राष्ट्र जब इजराइल के हाथों बुरी तरह पीटे गये तब उन्होंने भी अपनी रक्षा सामर्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लक्ष्य से पाकिस्तान से मैत्री का हाथ बढ़ाया। इजराइल को पराजित कर अरब देशों की श्रेष्ठता स्थापित करने की महत्वाकांक्षा के परिणाम स्वरूप ही पाकिस्तान व

अरब राष्ट्रों ने सम्मिलित रूप से आणविक शक्ति की अनिवार्यता का अनुभव किया। यहीं से "इस्लामिक बम" के निर्माण की भावना ने जन्म लिया।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी अरब देशों ने अणु बम की खरीद के लिये लीबिया के प्रधानमंत्री को सन् 1971 में चीन भेजा था। लीबिया के कर्नल गददाफी ने फ्रान्स से भी इस सम्बन्ध में वार्ताएं की थी। इजिप्ट ने भी अरब राष्ट्रों के लिये परमाणु बम निर्माण कार्यक्रम हेतु अप्रत्यक्ष रूप से भारत से तकनीकी सहायता की प्राप्ति का प्रयत्न किया था किन्तु मुस्लिम देशों के सारे प्रयत्न निरर्थक रहे। फलतः पाकिस्तान ने परमाणु तकनीक में स्थापित अपनी तथाकथित श्रेष्ठता का विश्वास दिलाते हुए अरब राष्ट्रों से अपेक्षित धन प्राप्ति का आश्वासन लेकर "इस्लामिक बम" निर्माण का निर्णय ले लिया। इस परमाणु बम को "इस्लामिक बम" की संज्ञा देने के पीछे भी पाकिस्तान की गहरी कूटनीतिक चाल रही है। उक्त बम को इस्लामिक रंग देकर जहां एक ओर पाकिस्तान सम्पूर्ण मुस्लिम जगत को इस शक्ति से सुसम्पन्न करने की नीति पर चल रहा था वहीं इसकी आड़ में सम्पूर्ण इस्लामिक देशों का नेतृत्व करने की भी पाकिस्तानी महत्वाकांक्षी थी, जिससे विश्व-राजनीति में उसकी भूमिका को प्रमुखता मिल सके। इतना ही नहीं "मुस्लिम-ब्लाक" को विश्व-राजनीति में एक दबाव समूह के रूप में स्थापित करने की भी उसकी योजना है।

2 पाकिस्तानी परमाणु सुरक्षा कार्यक्रम:-

पाकिस्तान को यह पूर्ण विश्वास था कि यदि उसने "पाकिस्तानी परमाणु बम" निर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ किया तो

बड़ी शक्तियाँ उसकी आर्थिक व सैनिक सहायता बन्द कर सकती है जबकि विभिन्न मुस्लिम देशों से तेल आपूर्ति के कारण “इस्लाम बम” निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाना पश्चिमी देशों के लिये अपेक्षाकृत सरल नहीं होगा। मुस्लिम और अरब देशों के आर्शीवाद से अस्तित्व में आने वाली पाक बम योजना की गतिविधियां काफी रहस्यमयी रही हैं। इजराइल द्वारा इराकी रिक्टर “तामीज 1” के नष्ट करने के बाद पाक बम की स्थिति एक ऐसे इकलौते बेटे जैसी हो गयी जिसकी सुरक्षा एवं कार्यक्रम को जारी रखना पाकिस्तान की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वास्तव में परमाणु बम को ही कसौटी बनाकर मानवता को हिन्दू, मुस्लिम, यहूदी एवं ईसाइयों को अलग-अलग जमातों में बाटने वाले भुट्टो ने जब इस कार्यक्रम का श्रीगणेश किया था तब उनके मानस-पटल में शक्तिहीन मुसलमानों की बेहतरी और उनकी प्रतिष्ठा का ही ख्याल रहा होगा। परमाणु शक्ति अर्जित करके पाकिस्तान अपने परम्परागत व प्रथम श्रेणी के शत्रु भारत पर सामरिक श्रेष्ठता स्थापित करना चाहता था, जिससे भावी भारत-पाक युद्धों में परमाणु आक्रमण का भय दिखाकर कश्मीर सहित विभिन्न द्विपक्षीय मामलों का अपने अनुकूल हल ढूँढा जा सके। इतना ही नहीं, दक्षिण एशिया की प्रभावी शक्ति एवं विकासशील देशों की बिरादरी में भारत की स्थापित प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाकर क्षेत्रीय शक्ति का दर्जा प्राप्त करना भी पाकिस्तान के लक्ष्यों में से एक प्रमुख था।

2.1 भुट्टो-गददाफी और पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम

प्रथम भारतीय भूमिगत परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 पोखरण से पूर्व ही सन् 1972 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री भुट्टो ने पाकिस्तानी परमाणु विशेषज्ञों के एक

विशेष शिविर में येन केन प्रकारेण परमाणु शक्ति हासिल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। भुट्टो के प्रेस प्रवक्ता खलीद हसन के अनुसार “शिविर में परमाणु बम बनाने का निर्णय भुट्टो ने ऐसे सहज भाव से लिया था जैसे कि वह किसी चाय पार्टी का आयोजन करने जा रहे हों, जबकि सत्य यह था कि न तो बांग्लादेश युद्ध से आहत पाकिस्तान की माली हालत उसकी इजाजत देती थी और न ही इस क्षेत्र में पाकिस्तान की तकनीकी जानकारी। शायद बांग्लादेश में गवांयी प्रतिष्ठा पुनःपाने के लिये यही एक रास्ता उन्हें सूझा था।” फलतः भुट्टो ने बांग्लादेश में नैतिक व भौतिक रूप से बुरी तरह आहत पाकिस्तान को भारत के समकक्ष स्थापित करने के लक्ष्य से बम प्राप्ति हेतु कदम आगे बढ़ाया। भुट्टो ने न केवल इसे धार्मिक रंग दिया अपितु स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि “यदि भारत बम बनाता है तो हम पत्ते औ घांस खा लेंगे” यहाँ तक कि भूखे भी रह लेंगे, पर बम अवश्य बनायेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जर्जर अर्थ व्यवस्था के फलस्वरूप परमाणु कार्यक्रम का प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं था। फलतः भुट्टो ने इस्लामिक बम के निर्माण में अपेक्षित सहायता की प्राप्ति के उद्देश्य से दक्षिण, रबात, ट्यूनिंस और काहिरा की यात्राएं की किन्तु इस अभियान में वे असफल रहे। अन्ततः ट्रिपोली यात्रा के दौरान लीबिया के शासक कर्नल गददाफी व भुट्टो की भेट के दौरान जिन खोजा तिन पाइयां की कहावत चरित्रार्थ हुयी। कर्नल गददाफी के पास परमाणु तन्त्र बड़ा करने के लिये पर्याप्त धन तो था किन्तु तकनीकी ज्ञान के अभाव के इजराइलियों द्वारा इसे नष्ट किये जाने के भय के कारण ली बियाई परमाणु कार्यक्रम मूर्त रूप नहीं ले पा रहा था।



सन् 1974 में भुट्टो-गददाफी की भेट

सन् 1974 में भुट्टो-गददाफी वार्ता में यह तय हुआ कि बम बनाने के लिये लीबिया पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देगा और पाकिस्तान उस शक्ति के प्राप्त होने पर लीबिया को

उसके लाभ से कृतार्थ करेगा। लीबिया द्वारा पाकिस्तान को धन हस्तान्तरण की जो विधि अपनायी गयी वह जासूसी उपन्यासों में ही देखने को मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

की नजरों से बचकर परमाणु तन्त्र हासिल करने के लिये प्रेषित धन को बण्डलों में बांधकर पाकिस्तान भेजा गया। रोम से होकर कराची उड़ने वाले “पाकिस्तान इंटरनेशनल एअरलाइन्स” के इन जहाजों में कभी-कभी तो एक करोड़ तक के बण्डल होते थे। रोम स्थित पी0आई0एल0 के तत्कालीन मैनेजर मोहम्मद बेग के अनुसार इस विशाल धनराशि के सफल स्थानान्तरण के लिये अक्सर उन्हें इटालवी कस्टम के हाथ गरम करने पड़ते थे।

लीबिया से 60 करोड़ डालर प्राप्त होने के पश्चात् पाकिस्तान के समक्ष अब एक ही लक्ष्य था— कराची संयंत्र से प्राप्त परमाणु ईंधन से श्रम वर्धन हेतु एक यूरेनियम संयंत्र की प्राप्ति। फलतः पाकिस्तान ने जिसने भारत की ही भांति एन0पी0टी0 पर हस्ताक्षर नहीं किया है, फ्रान्स को अधिकारिक रूप से एक संयंत्र सप्लाई करने का आर्डर दे दिया। इसी बची पाकिस्तानी अधिकारियों ने इंग्लैण्ड, जर्मनी व हालैण्ड के सहकारी परियोजना— एलमेलो परमाणु केन्द्र में काम करने वाले एक पाकिस्तानी देशभक्त वैज्ञानिक डॉ0 अब्दुल कादिर खान के जरिये वे सब प्रयोग, विधियां एवं प्रक्रियाओं का विवरण प्राप्त कर लिया जो यूरेनियम संवर्धन के लिये आवश्यक होते हैं। किन्तु अमेरिकी एवं इजराइली गुप्तचरों द्वारा पाकिस्तानी गतिविधियों का भण्डाफोड़ होने के बाद उसका यह कार्यक्रम असफल रहा।

2.2 भुटटो-अल्ब्रेख्ट भिगेलूव्यापारिक समझौता

अमेरिकी विदेश मंत्री डॉ0 किसिंजर व राष्ट्रपति कार्टर ने 1979 मे एन0पी0टी0 पर हस्ताक्षर हेतु पाकिस्तान पर विशेष

दबाव डाला। सन् 1979 में पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक सहायता स्थगित कर दी गयी। इतना ही नहीं अमेरिका के प्रबल विरोध के कारण फ्रान्स ने पाकिस्तान को संयंत्र सप्लाई करने से इन्कार तो कर ही दिया साथ ही हालैण्ड की सुरक्षा पुलिस की पूछताछ के भय से काडूटा प्रायोगिक संयंत्र के संचालक डॉ0 खान को सह देश छोड़ना पड़ा। किन्तु तब तक पाकिस्तान के पास परमाणु बम निर्माण की पर्याप्त तकनीक सामग्री एकत्रित हो चुकी थी। यद्यपि फ्रान्स व बेल्जियम से प्राप्त विभिन्न आवश्यक उपकरणों, नाइजर से आयातित खनिज यूरेनियम एवं डॉ0 खान द्वारा चोरी छिपे लायी गयी तकनीक आदि के बल पर पाकिस्तान ने परमाणु कार्यक्रम प्रारम्भ किया। किन्तु विभिन्न स्त्रोतों से अपेक्षित साज-सामान एकत्रित करने की गतिविधियों का एक बार पुनः भण्डाफोड़ हो गया। पाक परमाणु विशेषज्ञों ने कनाहा की फर्म “सेराबिट इलेक्ट्रानिक्स लि0” को वो आर्डर दिये थे उनके कारण फर्म के तीन भागीदार मिस्त्र के एलगानयाबी, लेबनान के मो0 अहमद और पाकिस्तान के अब्दुल अजीज को बगैर सरकारी अनुमति के इलेक्ट्रानिक्स उपकरण निर्यात करने के लिये अदालत में हाजिर होना पड़ा। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर यह दूसरी चोट थी। फिर भी, पाकिस्तान के हौसले परत नहीं हुये। हां, लौकिक जिज्ञासा व ताक-झांक से तंग आकर इस्लामिक बम के विकास का कार्य अब कुछ और ही गुप्त व रहस्यमयी ढंग से आगे बढ़ा। यद्यपि इस कार्यक्रम के लिये पाकिस्तान ने कुछ उपकरण पश्चिमी जर्मनी से भी खरीदे थे, किन्तु उसका ध्यान मुख्यतः फ्रान्स पर ही केन्द्रित था।



Meeting between Zulfikar Ali Bhutto and Kennedy

बाद में तत्कालीन पाक प्रधानमंत्री श्री भुटटो ने जर्मन वैज्ञानिकों के सहयोगी रूख को देखते हुये जर्मनी, को आधार बनाकर पाकिस्तान बन निर्माण हेतु अपेक्षित वैक्यूम बम, अलम्यूनियम राडस्, रेडियो धर्मिता रक्षी पोशाकें, जनरेटर व

अन्य आवश्यक कल पुर्जे खरीदे। पाकिस्तान के इस गुप्त परमाणु कार्यक्रम में जर्मनी के एक विशेषज्ञ अल्ब्रेख्ट भिगेलू ने विशेष भूमिका निभायी। इस्लामिक बम की कहानी के साथ-साथ पाकिस्तान और भिगूले के बीच व्यापारिक समझौता

की एक ऐसी कहानी है जिसमें पाकिस्तान ने इस विदेशी पर अपने इरादे एकाएक न थोप कर शनैः शनैः अपने इरादे स्पष्ट किये।

भिगूले और पाकिस्तान के बीच पहला समझौता 13 नवम्बर 1976 को हुआ जिसके अन्तर्गत देश में एक फलूरायड कारखाना बनाने के लिये 4-5 करोड़ मार्क का आर्डर कराची के एक कपड़ा उद्योग से मिला। इसके लगभग 5 माह बाद 3 जनवरी 1977 को उसने एक दूसरा समझौता पाक सरकार के साथ किया जिसमें उस पाकिस्तान के लिये एक ऐसा संयंत्र बनाया जो प्रति वर्ष 198 टन यूरेनियम हेक्साफ्लूरायड और

178 टन टेट्राफ्लूरायड पैदा कर सके। आर्डर का 20 प्रतिशत उसे शीघ्र भुगतान कर दिया गया। शेष धनराशि काम पूरा हो जाने पर देने का वचन दिया गया। इस सम्बन्ध में अन्तिम किन्तु महत्वपूर्ण समझौता 9 मार्च 1977 को हुआ। एक (प्रत्यक्ष) गवाह के अनुसार—इस्लामाबाद से कुछ किलोमीटर दूर जिस विक्टोरियन शैली के बंगले में यह समझौता हुआ था उस बंगले के बाहर हर पेड़ के नीचे एक सन्तरी तैनात था। समझौता “से0ई0एस0 काल्टहौफ (प्रा0) लिमिटेड” के संचालक भिगूले और मेसर्स अरशद, अमजद, आबिद लिमिटेड के प्रतिनिधि हारून फारूक, यौसी और डॉ0 जावेद के बीच हुआ।



समझौतों पर हस्ताक्षर के दौरान एक उच्च पाक अधिकारी और दो अन्य जर्मन विशेषज्ञ भी वहां उपस्थित थे। पहले से ही तैयार इस समझौते के प्रपत्र पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद श्री फारूक ने कहा कि “यह हमारी और हमारी कौंगी तारीख की एक अहम घड़ी है।” समझौते के अन्तर्गत भिगूले को मेसर्स अ0अ0अ0 लिमिटेड को छड़ के आकार के 99% संवर्धित यूरेनियम (यूरेनियम-235) सप्लाई करना था। इस स्तर के यूरेनियम का व्यापारिक रिएक्टरों में कोई उपयोग नहीं है। अतएव इसका एक ही उद्देश्य हो सकता था—परमाणु बम का निर्माण। समझौते के दौरान म्यूनिख के प्रसिद्ध शस्त्र उद्योग के लिये क्लोराइड संयंत्र के रसायन विशेषज्ञ एरविंग वैल्डुग एवं कार्ल्सरुहे की उपस्थिति से भी यह स्पष्ट है कि यह समझौते काफी महत्वपूर्ण थी। उल्लेखनीय है कि एवरिंग वैल्डुंग ने जहां एक ओर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राकेट छोड़ने के लिये फार से ईंधन तैयार किया था वहीं कार्ल्सरुहे ने पश्चिमी जर्मनी के (अब जर्मनी) कई अस्पतालों में परमाणु-चिकित्सा-विभाग स्थापित करने का सफल कार्य किया है। जर्मन विशेषज्ञों के सहयोग से न केवल जटिल उपकरणों, उनके निर्माण योजनाओं एवं प्रक्रिया विधियों का ही आयात पाकिस्तान में हुआ अपितु परीक्षण प्रयोग के लिये उन्हें जर्मनी भी लाया गया। कुछ प्रयोग तो पाक विशेषज्ञों ने स्वयं जर्मनी पाकर किये। जर्मनी के अतिरिक्त कनाडा से भी पाकिस्तान ने परमाणु बन निर्माण में काम आने

वाले अपेक्षित कल पुर्जे प्राप्त करने की कोशिशों की हैं। सन् 1980 में पाकिस्तान का एक उच्च स्तरीय दल कनाडा की एक मशीनी फर्म में परमाणु वैज्ञानिकों के रूप में कार्यरत ए0ए0खान से सम्पर्क किया। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान की परमाणु परियोजना के अध्यक्ष डॉ0 अब्दुल कादिर खान के पहले ही उसे पाकिस्तान में आकर कार्य करने का काफी लालच दिया था किन्तु वह इसके लिये तैयार नहीं हुआ। काफी प्रयत्नों के पश्चात् उसने पाकिस्तानी तस्कर दल को अपेक्षित सहायता का आश्वासन अवश्य दिया। यही कारण है कि जब उक्त पाकिस्तानी तस्कर दल कनाडा पहुंचा तब ए0ए0खान ने न केवल विभिन्न कम्पनियों के मालिकों से उसका परिचय करवाया अपितु यूरेनियम के परिशीघन में काम आने वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्र एवं तीव्र गति वाले परिवर्तक यन्त्रों को पश्चिमी देशों के माध्यम से पाकिस्तान भेजने की व्यवस्था भी की। इन उपकरणों का निर्माण प्रसिद्ध अमेरिकी कम्पनियों—जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वी0सी0ए0 कार्पोरेशन एवं मोटरेटा इन कार्पोरेशन द्वारा किया गया था। किन्तु कनाडा पुलिस व गुप्तचरों को खान की गतिविधियों की सूचना मिल गयी। फलतः परमाणु उपकरणों सहित 19 पेटियां माण्ड्रियाल हवाई अड्डे पर पकड़ ली गयी। इसमें माल सहित खान स्टोर के मालिक व एक इंजीनियर मोहम्मद अहमद भी गिरफ्तार हुये थे। कनाडा में सऊदी अरब के पासपोर्ट पर रहे पाकिस्तानी नागरिक साद गग्र की भी परमाणु तस्करी में महत्वपूर्ण भूमिका

रही है। ज्ञातव्य है कि 1982 में जब पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक कनाडा की यात्रा पर गये थे तो उस समय राजकीय आतिथ्य को त्याग कर वे दो दिनों तक साद गब्र के घर पर रुके। इसी के माध्यम से ही कनाडा से पाकिस्तानी साद गब्र के ही निमन्त्रण पर अमेरिका भेजे गये एक और पाकिस्तानी परमाणु जासूस नजीर अहमद वैद ने भी टेक्सास के ह्यूस्टन स्थान पर अपना अड़डा बनाकर परमाणु उपकरण की तस्करी का कार्य सफलता के साथ सम्पादित किया। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के जासूस स्विटजरलैण्ड में भी सक्रिय रहे हैं। इस बात के ठोस परमाणु हैं कि स्विटजरलैण्ड की एक फर्म ने पाकिस्तान को एक ऐसा संयंत्र बेचा है जो सेप्टीपयूज मशीन में ईंधन डालने एवं उसमें से वापस निकालने का कार्य कर सकता है। जर्मनी से भी ठोस यूरेनियम को गैसीय विधि द्वारा हेक्साफ्लोराइड में परिवर्तित करने वाले एक संयंत्र को भी पाकिस्तान ने आयात किया है। चोरी छिपे विभिन्न यूरोपीय देशों से परमाणु बम निर्माण में काम आने वाले विभिन्न धातुओं, कल पुर्जा व उपकरणों की आपूर्ति तथा कहुटा व चश्मा की इकाइयों के चालू हो जाने के बाद फरवरी 1984 में कादिर खां ने घोषणा की कि "पाकिस्तान यूरेनियम का संवर्धन कर सकता है तथा यदि आवश्यकता हो तो अपना बम भी बना सकता है। अमेरिकी सीनेटर ने विभिन्न प्रमाणों को एकत्रित करने के बाद यह बताया कि "पाकिस्तान ने कहुटा में न केवल संवर्धन सुविधा का विस्तार कर लिया है अपितु उसने चीन तथा अन्य पश्चिमी देशों से कल पुर्जा आयात करके इस्लामाबाद के निकट पिनस्टेक की निलोर प्रयोगशाला में पुर्नपरिष्करण सुविधा चालू करके वह शस्त्र-श्रेणी के प्लूटोनियम की प्राप्ति में सफल हो गया है। पाकिस्तान की यह क्षमता देखकर अमेरिका द्वारा उसपर डाले जा रहे विभिन्न दबावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये 1984 में जनरल जियाउल हक ने कहा कि "हमारे पास आणविक क्षमता तो है परन्तु हमारे वित्तीय साधन हमें बम बनाने की इजाजत नहीं देते। इसी बीच सितम्बर 1986 में पाकिस्तान द्वारा "क्राइटोन-स्वच" जिसका परमाणु विस्फोट में ट्रिगर के रूप में इस्तेमाल होता है, की तस्करी की अफवाहों से चिन्तित अमेरिका व सोवियत संघ ने पाकिस्तान को शस्त्रोन्मुख आणविक कार्यक्रम से विरत रहने की अपील की। किन्तु जनरल जिया ने पाकिस्तान पर लगाये जा रहे परमाणु-तस्करी घटनाओं को कपोलकल्पित बताते हुये 1986

में यह घोषणा की कि "हमारा कोई सैन्य कार्यक्रम नहीं है। लेकिन, नवम्बर 1986 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार बाब बुडवर्ड द्वारा "वाशिंगटन पोस्ट" के माध्यम से यह तथ्य प्रकाशित करने की पाकिस्तान ने 93.5% यूरेनियम संवर्धित करने के अतिरिक्त ट्रिगर परीक्षण भी कर लिया है, से पाकिस्तान के सहस्यमयी परमाणु कार्यक्रम की कलई खुल गयी। बुडवर्ड के अतिरिक्त लियोनार्ड स्पेक्टर, भारत के तत्कालीन विदेश सचिव ए0पी0वेंकटेशवरन तथा पाकिस्तान स्थित अमेरिकी राजदूत डीन हिण्टन आदि ने भी पाकिस्तान के आणविक कार्यक्रम पर चिन्ता व प्रतिक्रिया व्यक्त की। डीन हिण्टन ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को दिये गये पाकिस्तान के पास आणविक संयंत्र न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र पर रोष्पूर्ण टिप्पणी करते हुये कहा कि "क्या राष्ट्रपति कांग्रेस को यह प्रमाणित कर सकता है कि पाकिस्तान के पास आणविक संयंत्र नहीं है क्या इसका यह निष्कर्ष है कि पाकिस्तान के पास सभी आणविक विस्फोट यन्त्र के उपकरण हैं परन्तु उसने एसेम्बल नहीं किया है।

2.3 कहुटा प्रयोगशाला में उच्च श्रेणी का शस्त्र स्तरीय यूरेनियम संवर्धन कार्य

1 मार्च 1987 को इस्लामाबाद में भारत के प्रमुख पत्रकार कुलदीप नैययर व पाकिस्तानी बम के पितामह डॉ0 खान के मध्य सम्पन्न वार्ता से यह पुष्ट हो गया कि पाकिस्तान ने परमाणु बम निर्मित कर लिया है। इस वार्ता के दौरान डॉ0 खान ने बताया कि "सी0आई0ए0 यह कहती रही है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तथा विभिन्न समाचार पत्रों में भी यह खबर आतीरही है। अमेरिका इस बात को जानता है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। उन्होंने यह बताया कि बड़ी शक्तियां व भारत तथा इसराइल आदि कह रहे थे कि पाकिस्तान कभी भी परमाणु बम नहीं बना सकता किन्तु उन्हें यह मालूम होना चाहिये कि हमने ऐसा कर लिया है। प्रथम बार डॉ0 खान ने स्वीकार किया कि इस्लामाबाद से कुछ मील दूर स्थित कहुटा की प्रयोगशाला में उच्च श्रेणी का शस्त्र स्तरीय यूरेनियम संवर्धन कार्य सम्पन्न हो रहा है। जब नैययर ने उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट कर लिया है, तो उन्होंने बताया कि "क्या विस्फोट करना आवश्यक है यह परीक्षण केवल भूमि में ही नहीं अपितु सिमुलेटर की सहायता से प्रयोगशालाओं में भी सम्भव है।



हमें अमेरिकी सहायता की कटौती का भय है। लगभग 1 घण्टे के अपने साक्षात्कार में डॉ० खान ने गर्व के साथ बताया कि भारत ने अपने परमाणु परीक्षण में लगभग 12 वर्ष लगाये जबकि हमने मात्र सात वर्षों में परमाणु बम के कुल पुर्जे जोड़ लिये। उन्होंने कहा कि भारत के परमाणु बम पर शोध करके बिना परीक्षण किये ही बड़ा परमाणु बम निर्मित कर लिया है। कुलदीप नैययर के यह कहने पर कि "सन् 1974 में सम्पन्न भारतीय परमाणु विस्फोट शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये था, कादिर खां की प्रतिक्रिया थी कि आणविक कार्यक्रमों के साथ शान्तिपूर्ण शब्द जोड़ना साफ-साफ धोखा है तथा कोई भी बम शान्तिपूर्ण नहीं होता है। क्यूटा संयंत्र को अपने तृतीय बच्चे की तरह प्रिय मानने वाले डॉ० खान ने बताया "कि हम अपने आणविक कार्यक्रम की सफलता हेतु हर सम्भव प्रयत्नों का सहारा ले सकते हैं। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि "पाकिस्तान के अस्तित्व को कोई चुनौती दी गयी तो हम बम का प्रयोग भी कर सकते हैं। लन्दन के "आब्जर्वर" एवं अन्य समाचार पत्रों से नैययर-कादिर साक्षात्कार के प्रकाशित होने के बाद पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर हुई तीव्र अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए डॉ० कादिर खान ने बताया कि उन्होंने नैययर को कोई ऐसा साक्षात्कार नहीं दिया है। डॉ० कादिर खान ने बताया कि उनका परमाणु

कार्यक्रम पूर्णतः शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये है जिसके द्वारा हम अपने औद्योगिक विकास को त्वरित गति देने के लिये ऊर्जा का शान्तिपूर्ण प्रयोग करना चाहते हैं। पाकिस्तान के विदेश मन्त्रालय व तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने भी टाइम्स पत्रिका को दिये गये एक साक्षात्कार में कहा कि "आप इसे (परमाणु संत्र) सैन्य प्रयोजन के लिये भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने यह नहीं कहा कि हम इसमें असमर्थ हैं। हमने केवल इतना कहा है कि ऐसा न करने को न हमारा इरादा है और न ही हमारी इच्छा ही है आप आज निःसंकोच यह लिख सकते हैं कि पाकिस्तान जब चाहे बम (आणविक) बना सकता है। एक बम के बारे में क्या कठिनाई है। एक बार प्रौद्योगिकी प्राप्त कर लेने के बाद, जो पाकिस्तान के पास है, आप जो चाहे कर सकते हैं।

जनरल जिया द्वारा डॉ० कादिर खान के वक्तव्य का खण्डन कर देने के पश्चात् 10 जुलाई 1987 को अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक पाकिस्तानी नागरिक अरशद परवेज को फिलाडेलफिया में उस समय रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया जब वह 50,000 पौण्ड "मेरेजिंग-350" स्टील, जिसका प्रयोग सेण्ट्रीफ्यूज संयंत्रों में किया जाता है, पाकिस्तान को निर्यात करने का लाइसेंस लेने हेतु एक अमेरिकी अधिकारी को रिश्वत दे रहा था।



अमेरिकी कांग्रेस मैन स्टीफन सोलार्ज, मार्क तथा रिचर्ड कनेडी आदि ने पाकिस्तान की आणविक गतिविधियों पर चिन्ता प्रकट करते हुये पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी अमेरिकी सहायता स्थगित करने हेतु राष्ट्रपति रीगन पर दबाव डाला किन्तु इन सब की अनदेखी करते हुये अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने सन् 1988 हेतु पाकिस्तान को 480 अरब डॉलर की अमेरिकी सहायता देने की अनुमति देते हुये सिमिंग्टन व सोलार्ज संशोधन छूटों पर हस्ताक्षर कर दिये। बाद में पाकिस्तान स्थित एक अमेरिकी अधिकारी रिचर्ड बारलो ने यह रहस्योदघाटन किया कि "पाकिस्तान ने सन् 1987 में ही परमाणु बम का निर्माण कर लिया था किन्तु सोवियत संघ के विरुद्ध अफगान मुजाहिदीनों की पाक-सहायता के फलस्वरूप अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जान बूझकर इसकी अनदेखी की गयी। जून 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने अमेरिकी की यात्रा के दौरान यह संकेत दिया था कि "1990 में पाकिस्तान शस्त्र श्रेणी के यूरेनियम का उत्पादन प्रारम्भ कर देगा। जहां तक पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों का सन्दर्भ है, उसका प्रथम परमाणु संयंत्र "कान्नुप" कराची से 13 किलोमीटर पश्चिम बुलैजी तट पर स्थित है। कहेटा में, इस्लामाबाद से लगभग 25 किलोमीटर दूर, पाकिस्तान का प्रमुख यूरेनियम परिष्कृत करने वाला संयंत्र है जो डॉ० अब्दुल कादिर खान की देखरेख में कार्य कर रहा है। इसके अलावा व्यगा, मुलतान, लाहौर, कराची आदि में भी उसके विभिन्न परमाणु संयंत्र कार्य कर रहे हैं। कहेटा पाकिस्तान का प्रमुख परमाणु संयंत्र है, जहां वह प्रति वर्ष 45-75 किलोग्राम शस्त्र-स्तर यूरेनियम का उत्पादन हो रहा है। "यूरेनियम व प्लूटोनियम की एक विश्व खोजी संस्था के एक अनुमान के अनुसार सन् 1991 तक पाकिस्तान ने 130-220 किलोग्राम शस्त्र- स्तरीय यूरेनियम का उत्पादन कर लिया है। जनरल असलम बेग एवं बेनजीर भुट्टो के विभिन्न वक्तव्यों के

अतिरिक्त अगस्त 1994 में जर्मनी में हुयी प्लूटोनियम तस्करी में पाकिस्तानी हाथ होने तथा 23 अगस्त 1994 को पूर्व पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा की गयी घोषणा 'कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, से यह पुष्ट हो गया है कि अब पाकिस्तान परमाणु शस्त्र सम्पन्न राष्ट्र है। इसके अलावा अब अधिकारिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा उपमंत्री लिन डेविस द्वारा भी यह स्वीकार करने, कि पाकिस्तान के पास 15 परमाणु बम है, से पाकिस्तान के आणविक शस्त्र, विवाद की सत्यता की पुष्टि हो गयी है।

2.4 पाकिस्तानी आणविक तकनीकी क्षमता

मई 1980 में पाकिस्तान के "अन्तरिक्ष व वातावरण शीघ्र कमीशन के डाइरेक्टर डॉ० सलीम मसूद ने कहा था कि पाकिस्तान एक स्वदेश निर्मित बी०ए०डी०आर० नामक उपग्रह का प्रेक्षण करने वाला है। यद्यपि उस समय यह स्पष्ट नहीं हो पाया था किन्तु जनवरी 1989 में विभिन्न स्रोतों से इसकी पुष्टि हो गयी थी कि उक्त उपग्रह की प्रक्षेपित करने वाले "रेनुमा" व "शमर" नामक राकेटों का निर्माण पाकिस्तान द्वारा "वाह" व "एबोटाबाद" के महत्वपूर्ण इलाके में चीन के सहयोग से किया जा रहा है। सन् 1989 में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असलम बेग ने राष्ट्रीय रक्षा कालेज, इस्लामाबाद में सैनिकों को सम्बोधित करते हुये बताया था कि बलूचिस्तान स्थित "मकरान" स्थल पर पाकिस्तान दो मिसाइलों जिनकी रेंज क्रमशः 80 व 300 किलोमीटर है, का सफल परीक्षण कर चुका है। इन मिसाइलों को हत्फ-1 व हत्फ-2 नाम दिया गया। उल्लेखनीय है कि यह नामकरण मुस्लिमों के पैगम्बर की तलवारों के नाम पर आधारित है। इन मिसाइलों के अतिरिक्त पाकिस्तान ने 25 अप्रैल 1988 को कराची के निकट साोनमियानी परीक्षण केन्द्र से 640 किलोमीटर



हत्फ-1 प्रक्षेपात्र



हत्फ-2 प्रक्षेपात्र

दूरी तक 150 किलोग्राम भार वहन करने वाले राकेट का सफल परीक्षण भी कर लिया है। पाकिस्तान द्वारा इन मिसाइलों के निर्माण एवं इनके सफल प्रक्षेपण से भारतीय प्रतिरक्षा व्यवस्था एवं दक्षिण एशिया के रणनीतिक परिदृश्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। किन्तु उसके द्वारा परमाणु अस्त्र क्षमता हासिल कर लेने से हत्फ-1 व हत्फ-2 का सामरिक महत्व काफी बढ़ गया है। मई 1988 में अमेरिकी सिनेटर डेनियल क्वाले ने तृतीय विश्व में बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार से सम्बन्ध में अपनी एक प्रकाशित रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान द्वारा निर्मित हत्फ मिसाइलें चीन के ग्रेल मिसाइल की तकनीक पर निर्मित की गयी है तथा चीनी वैज्ञानिकों व तकनीशियनों ने पाकिस्तानी मिसाइल निर्माण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सहायता दी है। इस बात की भी प्रबल सम्भावना है कि पश्चिमी जर्मनी (अब संयुक्त जर्मनी) की एक प्राइवेट कम्पनी ओट्राग जिसने सन् 1978 में जेयरे में एक परीक्षण रेन्ज की स्थापना के बाद ब्राजील व लीबिया में भी इसका विस्तार किया है, ने भी पाकिस्तान के राकेट विकास कार्यक्रम में सहायता की है।

2.5 पाकिस्तान के राकेट विकास कार्यक्रम में जर्मनी की भूमिका

पाकिस्तान के राकेट विकास कार्यक्रम में जर्मनी की भूमिका तथा चीनी मिसाइल एम-11 के तकनीकी स्वरूप पर निर्मित उक्त पाकिस्तानी राकेट से उसकी परमाणु शस्त्र क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हो गयी है। चीन के साथ स्थापित सैनिक

सम्बन्धों का लाभ उठाते हुये पाकिस्तानी विशेषज्ञ आई0आर0बी0एन0 के निर्माण की दिशा में अपना कदम बढ़ा रहे हैं। चीन द्वारा पाकिस्तान को नियति की गयी एम-11 बैलिस्टिक मिसाइलों से न केवल दक्षिण एशिया का रणनीतिक परिदृश्य भयावह हो गया है अपितु गुप-7 (ब्रिटेन, कनाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान एवं अमेरिका) द्वारा अप्रैल 1987 में स्थापित एम0टी0सी0आर0 (मिसाइल टेक्नोलाजी कन्ट्रोल रिजिम) की सफलता के समक्ष एक नया खतरा भी पैदा हो गया है। एम-11 मिसाइलें 500 किलोमीटर की दूरी तक मार सकती हैं किन्तु चीन का कहना है कि इनकी रेन्ज 300 किलोमीटर ही है। यद्यपि चीन, पाकिस्तान को मिसाइल बेचने की खबरों का खण्डन करता रहा है किन्तु अमेरिकी उपग्रहों द्वारा लिये गये मिसाइलों के चित्रों से इसकी पुष्टि हो गयी है जिसे अन्ततः पाकिस्तान को स्वीकार करना पड़ा। जून 1991 में अमेरिकी उप विदेश मन्त्री रेजीनाल्ड बार्थोलोम्यु ने अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान चीन सरकार को यह समझाने की कोशिश की थी कि वह पाकिस्तान व सीरिया को ऐसी मिसाइल न बेचे। वास्तव में अमेरिका सीरिया की प्राप्त हो रही चीनी मिसाइलों से चिन्तित था क्योंकि सीरिया को चीनी मिसाइलों की प्राप्ति से इजरायल पर सामरिक दबाव बढ़ जायेगा, जिसे अमेरिका कभी सहन नहीं कर सकता। अमेरिकी विरोध के बावजूद चीन द्वारा पाकिस्तान को दी जा रही एम-11 मिसाइलों से भारतीय उपमहाद्वीप का सामरिक समीकरण प्रभावित हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान इन मिसाइलों से भारत के प्रमुख शहरों पर आक्रमण कर सकता है।



हत्फ-3 प्रक्षेपात्र एम-11 मिसाइलों का पाकिस्तान ने हत्फ-3 नाम दिया

भारत को सर्वाधिक चिन्ता तो इस बात की है कि यह मिसाइलें परमाणु बमों को वहन करने में समर्थ हैं। अमेरिका की गुप्तचर एजेंसियों का तो यहां तक कहना है कि पाकिस्तान ने इन्हें परमाणु बमों से लैस भी कर लिया है। चीन द्वारा तृतीय विश्व के देशों को निर्यात मिसाइलों के सन्दर्भ में विस्तृत लेखा-जोखा पहले भी कई बार प्रकाशित किया जा चुका है। चीन द्वारा प्राप्त एम-11 मिसाइलों का पाकिस्तान ने

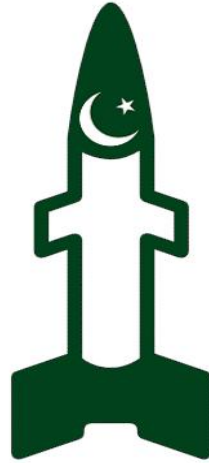
हत्फ-3 नाम दिया है। रक्षा सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान को अब तक 60 एम-11 मिसाइलें मिल चुकी हैं और उसने एक पूरी मिसाइल ब्रिगेड स्थापित कर ली है। शस्त्र विशेषज्ञों की यह मान्यता है कि यह मिसाइलें अचूक प्रहार नहीं कर सकती हैं किन्तु उनके विस्फोट शीर्ष में छोटे आकार के किन्तु भारी विस्फोट करने वाले सैकड़ों बमों को भरकर 15-20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत सैन्य-शिविरों को नष्ट किया जा

सकता है। पराजय की स्थिति में युद्ध के अन्तिम हथियार के रूप में इन मिसाइलों के माध्यम से शत्रु के इलाकों में परमाणु बम भी गिराये जा सकते हैं। यद्यपि पाकिस्तान की अपेक्षा भारत का मिसाइल विकास कार्यक्रम समुन्नत है किन्तु पाकिस्तान द्वारा तैयार अवस्था में एम-11 को खरीदकर अपने यहां तैयार कर लेने से भारतीय सीमाओं पर परमाणु दबाव चढ़ गया है।

3. पाकिस्तान की आणविक ईंधन क्षमता:—

पाकिस्तानी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में सर्वथा पारदर्शिता का अभाव दृष्टिगोचर होता है। सन् 1997 में मेमि इन्डाउमेन्ट फार इण्टरनेशनल पीस ने एक सर्वे अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि पाक की परमाणु ऊर्जा क्षमता के सम्बन्ध में पाकिस्तान द्वारा सूचनायें दबाकर रखी गयी हैं।

Pakistan's Nuclear Arsenal (estimates)



| Aircraft | Number of Warheads |
|-----------------|--------------------|
| F-16 A/B | 24 |
| Mirage III/V | 12 |
| SUBTOTAL | 36 |

Land-based ballistic missiles

| | |
|--------------------|-----------|
| Ghaznavi (Hatf-3) | 16 |
| Shaheen-1 (Hatf-4) | 16 |
| Shaheen-2 (Hatf-6) | 8 |
| Ghauri (Hatf-5) | 40 |
| NASR (Hatf-9) | 6 |
| SUBTOTAL | 86 |

Cruise missiles

| | |
|----------------|---|
| Babur (Hatf-7) | 8 |
|----------------|---|

Pakistan's missile capabilities (for a 500-kg payload)

| Missile | Origin | Lift-off weight | Length | Diameter | Fuel | Stages | Range | Status |
|-------------------|------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|--------|-----------|------------------------|
| Hatf-1 | French | 1,500 kg | 6m | 0.55m | Solid | 1 | 60 km | Deployed |
| Hatf-2 | French | 2,520 kg | 9.75m | 0.55m | Solid | 2 | 280 km | Deployed |
| Shaheen (Hatf-3?) | Chinese (M-9?) | 6,200 kg | 9.1m | 1.0m | Solid | 2 | 600 km | In developmental stage |
| Ghauri-1 (Hatf-5) | North Korea (No Dong-1) | 16 tonnes | 12.4m | 1.3m | Liquid | 1 | 800 km | In developmental stage |
| Ghauri-2 (Hatf-5) | North Korea (No Dong-1?) | N.A. | N.A. | N.A. | Liquid | 1 | 1,000 km | In developmental stage |
| Ghaznavi | North Korea? (Taepo Dong-1) | N.A. | N.A. | N.A. | Liquid | 2 | 2,000 km? | N.A. |
| Abdall | North Korea? (Taepo Dong-2?) | N.A. | N.A. | N.A. | Liquid | 2 | 3,500 km? | N.A. |

सर्वेक्षण ने यह भी संकेत दिया कि देश में विभिन्न स्थानों पर असुरक्षित परमाणु उपकरण कार्यरत हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पाकिस्तानी परमाणु संस्थान निम्नलिखित हैं—

1. चगाई पहाड़ी— सम्भावित न्यूक्लियर परीक्षण स्थल।
2. कराची— कनाडा द्वारा आपूर्तित परमाणु शक्ति रिएक्टर।
3. सरगोधा— भूमि से भूमि में मार करने वाली मिसाइलों को एकत्रित करने की सुविधा।
4. कहुटा— खान अनुसंधान प्रयोगशाला— यूरेनियम संवर्धन का शीर्षक यन्त्र यहां लगा है जो परमाणु बम

में प्रयोग किये जाने वाले संवर्धित यूरेनियम की नियमित पूर्ति के लिए सक्षम है।

5. गोलरा— यूरेनियम संवर्धन का संयंत्र यहां लगा है। साथ ही साथ शीघ्र और विकास की सुविधायें यहां उपलब्ध हैं। इस केन्द्र की विशेषता है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग के निरीक्षण के अन्तर्गत नहीं आता है।
6. तारवानाह— प्रक्षेपास्त्र उत्पादन कारखाना।
7. खुशाब— यहां प्लूटोनियम निर्माण करने वाले रिएक्टर बड़ी मात्रा में असुरक्षित परमाणु विस्फोटक प्लूटोनियम निर्मित करने में सक्षम है।

8. चश्मा-वृहद प्लूटोनियम उत्खनन संयंत्र तथा नागरिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं और चीन की ओर से दिया हुआ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है।

9. रावल पिण्डी- पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर साइंस एण्ड टेक्नोलाजी: प्रयोगशाला तथा प्लूटोनियम उत्खनन संयंत्र



1 चगाई पहाड़ी-न्यूक्लियर परीक्षण स्थल



2 कराची-कनाडा आपूर्ति परमाणु शक्ति रियेक्टर



3 सरगोधा-भूमि मिसाइलों परीक्षण स्थल



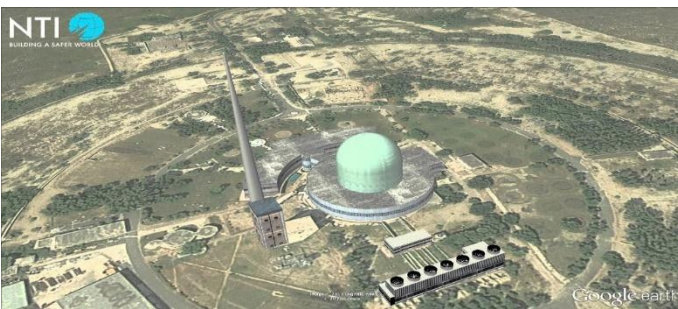
4 कहूटा- खान अनुसंधान प्रयोगशाला



5 गोलरा- यूरेनियम संवर्धन का संयंत्र



6.तारवानाह- प्रक्षेपास्त्र उत्पादन कारखाना।



7खुशाब-प्लूटोनियम निर्माण करने वाले रिएक्टर



8 चश्मा-वृहद प्लूटोनियम उत्खनन संयंत्र

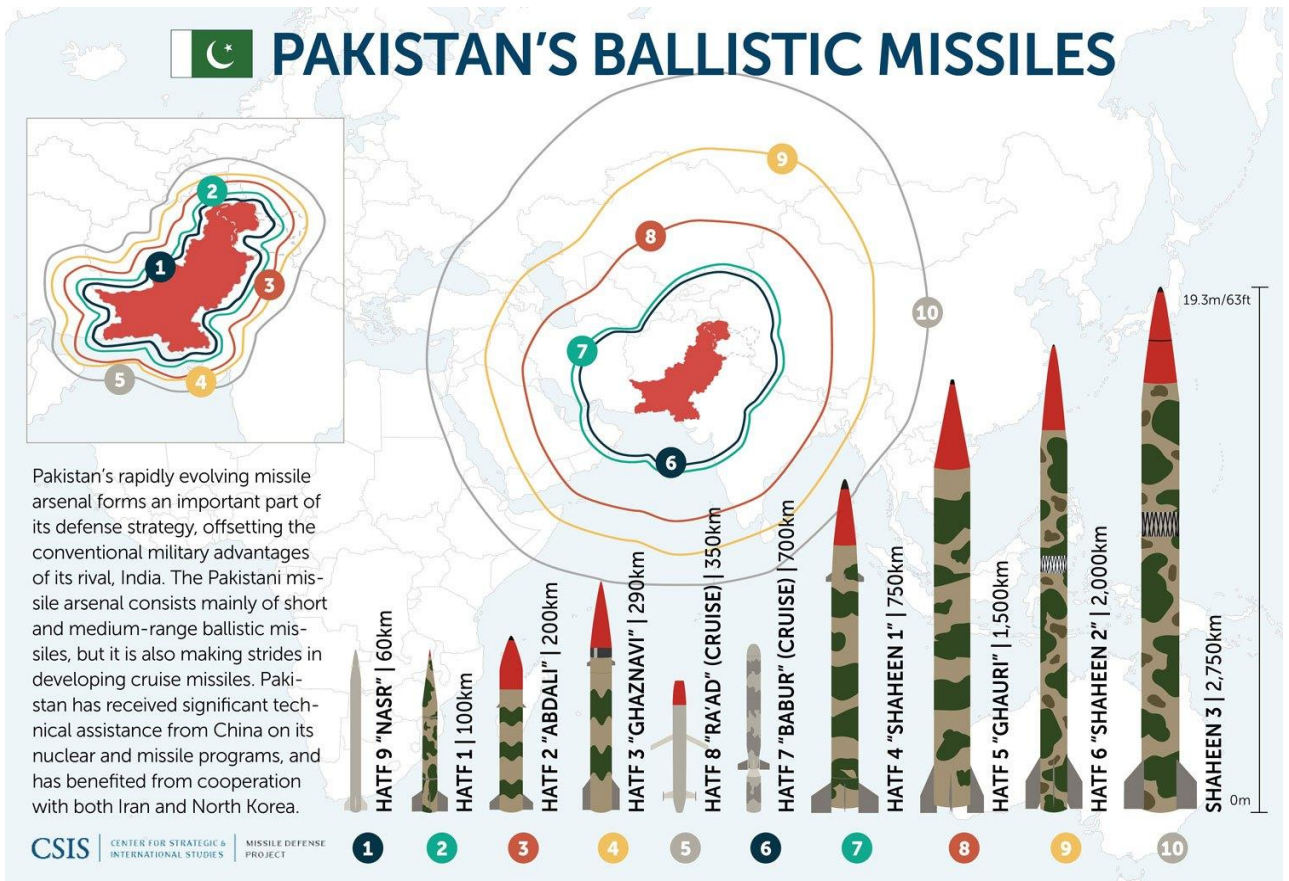


9. रावल पिण्डी— पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर साइंस एण्ड टेक्नोलाजी: प्रयोगशाला

4. वर्तमान में भारत-पाकिस्तान की आणविक ईंधन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन एव आवश्यकता:-

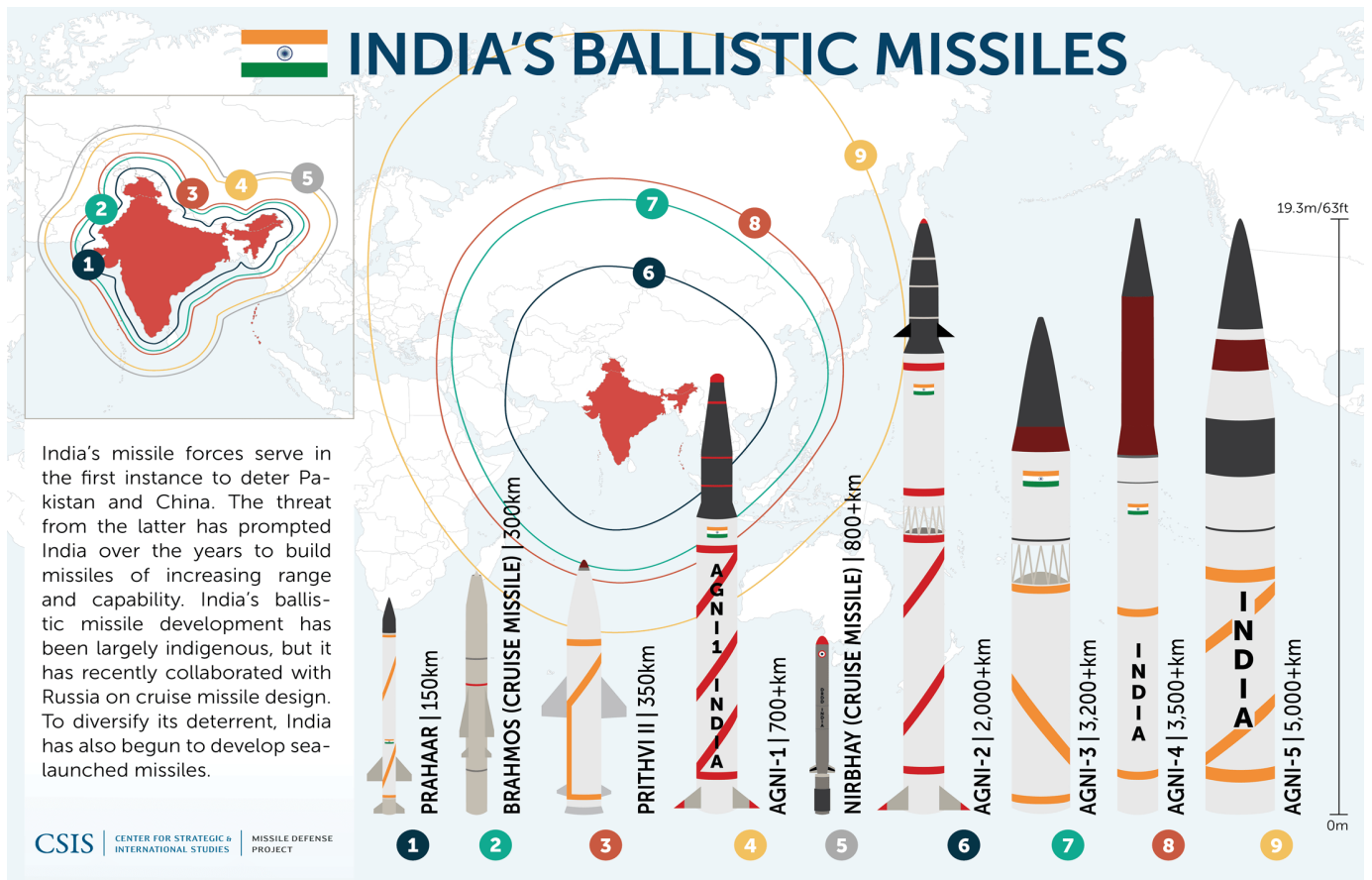
यद्यपि पाकिस्तान की अपेक्षा भारत का मिसाइल विकास कार्यक्रम समुन्नत है परन्तु उनके विस्फोट शीर्ष में छोटे आकार के किन्तु भारी विस्फोट करने वाले हौरक्षा सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने एक पूरी मिसाइल ब्रिगेड स्थापित कर ली है।

शस्त्र विशेषज्ञों की यह मान्यता है कि यह मिसाइलें कि अचूक प्रहार हैं अतएव, पाकिस्तान की सैन्य क्षमता में इस असाधारण वृद्धि को देखते हुए भारत ने अपने मिसाइल कार्यक्रम को मात्र तकनीकी प्रदर्शन तक ही सीमित न रखकर अपनी रक्षा सेनाओं को इससे (मिसाइलों) से सुसज्जित कर लिया है।



यद्यपि भारत ने "अग्नि", "पृथ्वी", "आकाश", "त्रिशुल" व "नाग" जैसे महत्वपूर्ण प्रक्षेपात्रों का सफल परीक्षण कर लिया है किन्तु परमाणु हथियार निर्मित न करने के अपने पूर्ण

निर्णय पर स्थिर भारत की उक्त मिसाइलों से दक्षिण एशियाई देशों को परमाणु आक्रमण से भयभीत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।



नैतिक व भौतिक रूप से बुरी तरह आहत पाकिस्तान स्वयं को भारत के समकक्ष स्थापित करने के लक्ष्य से परमाणु

बम प्राप्ति हेतु कदम आगे बढ़ाया। परन्तु भारत के अस्तित्व को कोई चुनौती दी गयी तो हम बम का प्रयोग भी कर सकते हैं।

Reference

- डी0के0 पलित एवं पी0के0एस0 नामबूदरी: पाकिस्तान का इस्लामिक बम, पृ0 1-20
- Levy, Adrian and Catherine Scott-Clark, Deception: Pakistan, the United States, and the Secret Trade in Nuclear Weapons. New York. Walker Publishing Company. 1977: page 112.
- जेड0ए0भुटटो।
- आर0आर0 सुब्रहम्यम: इण्डिया, पाकिस्तान, चाइना: डिफेन्स एण्ड न्यूक्लर अंगिल इन साउथ एशिया, पृ0 141
- वाशिंगटन टाइम्स जुलाई 12, 1984 डॉ0ए0क्यू0 खान पाकिस्तानी बाम्ब बाई श्रीधर, पृ0 173
- स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, मई 1987
- श्रीधर: डॉ0ए0क्यू0खान आन पाकिस्तान बाम्ब पृ0 152-155
- "Pakistan's Nuclear Bomb Program ,Volha Charnysh,3 September 2009.
- Information Bank Abstracts, New York Times, 8 June 1974
- Samina Ahmed, "Pakistan's Nuclear Weapons Program: Turning Points and Nuclear Choices," International Security, volume 23, issue 4, pages 178-204, Spring 1999: 181.
- Don Oberdorfer, Michael Gatier, and Maralee Schwartz, "Pakistan: The Quest for Atomic Bomb; Problem Discussed by West, Moscow, Peking," Washington Post, 27 August 1979, First Section, A1; in Lexis-Nexis Academic Universe, 27 August 1979
- टाइम्स 30 मार्च 1987 साइटेड इन डॉ0 ए0क्यू0खान आन पाकिस्तानी बाम्ब एडिटेड बाई श्रीधर, पृ0 176
- स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, फरवरी 1991
- जनरल, मिर्जा असलम बेग, न्यूक्लियर प्रोग्राम एण्ड पालिसिस रैम्बलिंग्स, डिफेन्स, जनरल वालूम 19 सं0 11-12, 1993 पृ0 20
- मशोहिद हुसैन, "बाल नाऊ इन पाकिस्तान कोर्ट", दी नेशन नवम्बर 29, 1990
- स्टाकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1992 पृ0 165
- इण्डिया टुडे, 1-5 सितम्बर, 1994
- नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1995
- द टाइम्स आफ इण्डिया, मई 1998

20. Sharon Otterman and Jayshree Bajoria, "Controls on Pakistan's Nuclear Technology," February 20, 2008.
21. [https://www.indiatoday.in/world/story/india-has-capability-to-make-2600-nuclear-weapons-](https://www.indiatoday.in/world/story/india-has-capability-to-make-2600-nuclear-weapons-pakistan-977869-2017-05-18)
22. [pakistan-977869-2017-05-18](https://www.indiatoday.in/world/story/india-has-capability-to-make-2600-nuclear-weapons-pakistan-977869-2017-05-18)
23. Google wikipedia.